भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2267
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

पोषण अभियान

2267. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में पोषण अभियान के मुख्य लक्ष्यों को हासिल कर पाई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) उक्त राज्य में जिला-वार कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ अभी पोषण अभियान चलाया जा रहा है; और
(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में इस योजना के नतीजों पर कोई मूल्यांकन/अध्ययन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष सहित ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): पोषण अभियान 2018 में शुरू किया गया था, जिसे आंगनवाड़ी सेवाओं और किशोरियों के लिए योजना (14-18 वर्ष, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में) के साथ व्यापक सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के अंतर्गत मिला दिया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं-चयन की व्यापक योजना है जो सभी पात्र लाभार्थियों अर्थात् 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, प्रसव के बाद 6 महीने तक स्तनपान कराने वाली माताओं और देश के पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में रहने वाली किशोरियों

(14-18 वर्ष की आयु) के लिए है। यह मिशन तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता तथा अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना

(ख) : तमिलनाडु राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन की जिलावार स्थिति https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है। तमिलनाडु राज्य में कुल 54,481 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं।

(ग) : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरे भारत में घरों के प्रतिनिधि नमूनों पर किया जाने वाला एक व्यापक, कई चरणों वाला सर्वेक्षण है। यह प्रजनन, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथाएँ, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग और उनकी गुणवत्ता से संबंधित रिपोर्ट प्रदान करता है। वर्ष 1992–93 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौरौं ने भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया है। एनएफएचएस–1 से एनएफएचएस–5 तक इन संकेतकों का विवरण निम्नानुसार है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**बौनापन %**	**अल्प वजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस 1-(1992-93) *	52	53.4	17.5
एनएफएचएस 2-(1998-99) **	45.5	47	15.5
एनएफएचएस 1-(2005-06) ***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस 1-(2015-16) ***	38.4	35.8	21.0

एनएफएचएस 1-(2019-21) ***	35.5	32.1	19.3
एनएफएचएस 1-(2025) ***	33.54	14.41	5.03

*4 वर्ष से कम
**3 वर्ष से कम
***5 वर्ष से कम

ऊपर उल्लिखित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों तथा पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार हुआ है।

इसके अलावा, पोषण ट्रैकर से प्राप्त तमिलनाडु राज्य में पोषण संकेतकों की स्थिति और पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार को नीचे देखा जा सकता है:

पोषण ट्रैकर से प्राप्त तमिलनाडु राज्य के पोषण संबंधी आंकड़े				
संकेतक	**अक्तूबर-2022**	**अक्तूबर-2023**	**अक्तूबर-2024**	**अक्तूबर-2025**
ठिगने बच्चे (%)	22.59	16.57	13.39	11.56
दुबले बच्चे (%)	6.05	4.75	3.57	3.32
अल्प वजन वाले बच्चे (%)	10.53	8.08	7.06	5.77

वर्ष 2021 में, विश्व बैंक ने पोषण सेवाओं की प्रदायगी कार्यक्रम का आकलन करने के लिए 11 प्राथमिकता वाले राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में एक सर्वेक्षण किया। निष्कर्षों से यह पता चला कि पोषण अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ - अर्थात् संबंधित संदेशों की प्राप्ति, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गृह दौरे तथा समुदाय-आधारित आयोजनों में सहभागिता आदि— बेहतर पोषण व्यवहारों से संबंधित थीं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि इस कार्यक्रम के पोषण संदेश 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं तक पहुँचे, और 81 प्रतिशत महिलाओं ने पहले छह महीनों तक शिशु को केवल स्तनपान कराया।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 और वर्ष 2025 में सक्षम आंगनवाड़ी पोषण अभियान का भी तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभावी आकलन किया गया, और इसमें पाया गया कि यह कार्यक्रम तमिलनाडु सहित देश में कुपोषण से निपटने के लिए प्रासंगिक और संतोषजनक है।

*****